दिशा में और अधिक करने की जरूरत है। कई कमेटीज भी बैठाई है, स्टडी की हैं। उसकी रिकमेंडेशंस इम्पलीमेंट की है। मैं फर्दर इम्पलीमेंट पर जोर दे रहा हूं कि जो लासेज है या डमेजेज हैं उनको कम से कम किया जाए और अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए। मैं चाहता हूं फर्दर इम्प्रूवमेंट किया जाये और कुछ इम्प्रूवमेंट की गयी है।

DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Sir, I would also like to know how many surprise checks have actually been made and what is the result of that.

श्री एच०के०एल० भगत: अचानक मैंने गोडाउन मे जा कर जाच की है। मैंने गोडाउन को विजिट किया है। जब मैं किसी राज्य में गया हूं तो मैंने वहा कहा कि आप अपना गोडाउन दिखलाइये। (व्यवधान) वीरेन्द्र वर्मा जी आप मुझ से ज्यादा जानते है। हम आप से रोज समझते है, सीखते हैं। मै अभी तीन दिन पहले हैदराबाद में गया था। मैंने उनसे कहा कि चलिए आपका गोडाउन देखता हूं। इसी प्रकार से मैंने और राज्यों के गोडाउन देख। वहा जाकर मैं अचानक गोडाउन के किसी हिस्से मे चला गया और कहा कि कितना स्टाक है दिखाइये। फिर मैंने पूछा कि यह कितने माल पुराना है, कितना इशुएबल है और कितना नहीं है, इसके लिए क्या कर रहे है और कौन से स्टैप उठा रहे हैं। इस तरह से मैंने कई गोडाउन देखें। जैसा मैंने कहा कि कुछ सन्तोषजनक कदम उठाये गये हैं। किसी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है और बचत भी हुई है। लेकिन कुछ और ज्यादा तेजी से कदम उठाना चाहता हूं। इसमें विजिलेंस की ज्यादा जरूरत है ऐसा मैं समझता हूं। कुछ केसेज में कार्रवाई की गयी है। मैंने सब को कहा कि ज्यादा चौकस रहिये और तेजी से कदम उठाइये जिससे लासेज और डेमेजज दोनों को कम किया जा सके।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि एक अरब 51 करोड़ रुपये जो आपने बताया है इस नुक्सान में ओपन वैगन में कितने प्रतिशत एफ० सी० आई० का अनाज ढोया गया है और इसके क्या कारण है?

श्री एच० के० एल० भगत: मेरे पास इस समय परसेंटज तो है लेकिन ढूढने मे ही सारा समय गुजर जायेगा। ओपन वैगन मे किसी हद तक नुकसान हुआ है लेकिन भेजना पड़ता है। टोटल लासेज की फिगर्स तो आपने पकड़ ली। आपने यह नही बताया कि लासेज कितना टोटल टर्नओवर में हुआ। इसमें लॉस कितना परसेंटज में गया? मैं बताता हू कि तीन क्वाइंट कुछ से दो क्वाइंट कुछ या एक क्वाइंट कुछ पर आ गया है। लासेज कम हुआ है यह ओपन वैगन में हुआ है। ओपन वैगन में इसलिए भेजना पड़ता है स्टोर मे समय पर पहुंच जाये। इस ड्राउट के समय में कमी के बावजूद यह सिस्टम ज्यादा समझ में आया। हमने यही देखा कि गवर्नमेंट का फैसला प्रोक्योरमेंट का डिस्ट्रिब्यूशन का सिस्टम लोगों के हित में है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: इस गरीब देश के लिए 151 करोड़ रुपये का कोई लॉस कम रकम नहीं है।

श्री एच० के० एल० भगत: मैंने नही कहा कि यह कम है। हजारों, करोड़ की कमी है। आप को मालूम है कि हजारों, करोड़ों की कमी है बतलाइये अपने घरों में, आपके खर्चों में कितना नुकसान हुआ है (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Sale of imported oil

*203. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether the imported oil is proposed to be sold through auction

as reported in the Times of India dated 5th November, 1987 and if so, how the retail consumer prices are proposed to be controlled;

(b) whether during the period of shortages, till the country is totally self sufficient, the vanaspati manufacture will be stopped and all oil sold as refined oil through public distribution system irrespective of whether the imports are gifts or commercial;

(c) whether Government propose to take over all distribution to ensure that vegetable oil is not excessively released by statutory bodies like NDDB, STC and NAFED etc. in oil producting States like Gujarat, Andhra Pradesh which has resulted in depression of production in oil seeds; and

(d) whether all vegetable oil is proposed to be imported and released only through the Vegetable Oil Board set up by Government?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H K. L BHAGAT): (a) Government has directed State Trading Corporation to sell imported edible oil through auction in open market. It is not proposed to control the retail consumer prices.

(b) No, Sir.

(c) Imported edible oils through State Trading Corporation are allocated to States for Public Distribution System keeping in view the demand from the States, prices and availability of indigenous edible oils. National Dairy Development Board (NDDB) also releases a small quantity of edible oils for sale through their outlets in open market and similarly NAFED distributes very small quantities of indigenous edible oils Releases are made keeping in view the interest of oilseed farmers.

(d) There is no such proposal under consideration.

IRDP allocation for Maharashtra

*204. SHRI NARESH C. PUGLIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the Integrated Rural Development Programme budget for the country for the year 1987-88,

(b) what is the allocation of funds granted for Maharashtra under the IRDP for the same period; and

(c) what is the amount of IRDP loan given to the people of Maharashtra for cattle development to encourage milk production during the same period?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI G S DHILLON): (a) The total Central budget provision for the Integrated Rural Development Programme for the country for 1987-88 is Rs. 310 crores.

(b) The total allocation for assisting families under IRDP in Maharashtra for 1987-88 is Rs 44 24 crores, of which the Central share amounts to Rs. 22.12 crores.

(c) During current year, upto October, 1987 loan of Rs. 812 64 lakhs was disbursed to the 25403 IRDP beneficiaries for purchase of milch cattle. Amount of subsidy is Rs. 389.68 lakhs.

DDA schemes for the weaker sections

*208. SHRI KAILASH PATI MISHRA:
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Slums Department of the Delhi Development Authority has utilised only Rs 1 09 crores out of the Rs. 24.30 crores allocated for 5 major schemes for the weaker sections during 1985-86 and 1986-87;